Bundelkhand Journal of Academic Research

भारत में सहकारी समितियों के प्रगति और प्रदर्शन का अध्ययन

पवन कुमार सिंह[1], डॉ. मुकेश कुमार[2]

1. **असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान),** सावित्री बाई फुले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चकिया, चंदौली।
2. **असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट।

(**Corresponding Author:** pavansinghgdc@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21625586

सारांश

एक सहकारी समिति समान जरूरतों वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है जो सामान्य आर्थिक हित को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं। इसका उद्देश्य आत्म–सहायता और आपसी मदद के सिद्धांत के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों के हितों की सेवा करना है। सहकारिता आर्थिक संगठन की एक महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती हैं। इसका मूल सिद्धान्त 'एक सबके लिए तथा सब एक के लिए' होता है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति सहकारी संगठन बनाकर अपने आर्थित हितों को आगे बढ़ा सकते है। इसमें कोई संदेह नही कि यदि सहकारी संस्थाओं को पर्याप्त कार्यकुशलता से संचालित किया जाए तो किसी भी प्रदेश का आर्थिक विकास अधिक तेजी से हो सकेगा, वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर ऊँचा होगा। सहकारी समितियां भारत में 8.44 लाख से अधिक सहकारी समितियां 30 से ज्यादा क्षेत्रों जैसे कृषि ऋण, डेयरी, मत्स्य पालन और आवास में सक्रिय हैं। ये ग्रामीण ऋण, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करती हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर वित्तीय सेवाओं को सुलभ बना रही हैं। वित्तीय समावेशन में योगदान सहकारी समितियां गरीब किसानों, ग्रामीण उद्यमियों और हाशिए पर रहने वाले समूहों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ती हैं, जिससे उनकी जीवन स्तर में सुधार होता है। ये ई–मार्केटप्लेस पर पंजीकरण और डिजिटल लेनदेन के माध्यम से बाजार पहुंच बढ़ाती हैं। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के तहत बहुउद्देशीय मॉडल और कंप्यूटरीकरण जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इससे वित्तीय समावेशन और अधिक प्रभावी बनेगा। यह शोध पत्र देश मे सहकारी समितियों का विकास, चुनौतियों एवं उसके समाधान अध्ययन किया गया है।

आलेख सूचना			
प्राप्त: 10 फरवरी, 2026	**स्वीकृत:** 27 फरवरी, 2026	**प्रकाशित:** 31 मार्च, 2026
सारणी: 01	**चित्र एवं ग्राफ:** 02	**स्रोत एवं संदर्भ:** 11
मुख्य शब्द:	समावेशन, सहकारिता, सशक्तिकरण, सामूहिक भागीदारी, सहकारी समिति।	

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि: हाल के वर्षों में, हमारे गाँव कई तरीकों से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ग्रामीण भारत के पुनरुत्थान के प्रेरणादायक मॉडल हमारे सामने हैं। खेतों और खलिहानों से आ रही आर्थिक बदलाव की हवा के पीछे सहकारी समितियाँ मुख्य उत्प्रेरक हैं। आधुनिक इतिहास पर नजर डालें तो भारत में सहकारी समितियों का इतिहास लगभग 120 साल पुराना है। प्राचीन ग्रंथ, प्रागैतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि सहयोग की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। भारत अपनी सहकारिता संस्कृति के पुनरुत्थान का साक्षी बन रहा है, जिसमें जमीनी स्तर की समितियाँ सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास के शक्तिशाली इंजन के रूप में उभर रही हैं। भारत में सहकारी समितियों की परिवर्तनकारी शक्ति का उल्लेखनीय उदाहरण राजस्थान की बोरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति है। बीते दशकों में यह कृषि के मूलभूत स्वरूप से आगे बढ़ते हुए काफी विकसित हो चुकी है। अब यह तीन शाखाओं के साथ एक मिनी बैंक का संचालन करती है और अकेले 2018–19 में इसने 4.55 करोड़ रुपये की जमा राशि जुटाई। आज भारत में लगभग 8,00,200 सहकारी समितियाँ हैं, जो पूरे देश में फैली हुई हैं और जिनके लगभग 300 मिलियन से अधिक सदस्य हैं। ये सहकारी समितियाँ कृषि प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, आवास, बुनाई, ऋण और विपणन सहित विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय हैं। सामूहिक भागीदारी के सिद्धांत पर काम करने वाली सहकारी समितियों की संख्या तेजी से

बढ़ रही है। सहकारी समितियाँ ग्रामीण भारत के 98 प्रतिशत हिस्से तक पहुँच चुकी हैं, और देश का 13 प्रतिशत रोजगार सीधे सहकारी समितियों द्वारा पैदा होता है। सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की यात्रा श्वेत क्रांति और हरित क्रांति के साथ शुरू हुई। गुजरात के आनंद में शुरू हुआ दूध सहकारी समितियों का एक प्रयोग आज अमूल के रूप में दुनिया का सबसे सफल सहकारी मॉडल बन गया है।

भारत के लगभग हर राज्य में दूध सहकारी समितियों का एक नेटवर्क विकसित हुआ है। देश में 200,000 सहकारी डेयरी समितियाँ हैं। ये किसानों को खेती के साथ–साथ आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान कर रही हैं। सहकारी समितियों ने जंगलों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ के माध्यम से वनवासी समुदायों में सामुदायिक विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। ट्राइफेड आदिवासी समुदायों को उनके उत्पादों को बेचने के लिए बाजार तक पहुँच प्रदान करके और वन उत्पादों के विकास में सहायता करके सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों को मजबूत कर रहा है। सहयोग के माध्यम से ग्राम स्वराज (गाँव के स्वशासन) की परिकल्पना को सही मायने में साकार करने के लिए, गाँव की सहकारी समितियाँ जैविक उर्वरक प्रदान करके डेयरी, उर्वरक, चीनी, शहद और ऊर्जा क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। आर्थिक सुरक्षा के बिना सामाजिक सशक्तिकरण का कोई भी प्रयास पूरा नहीं हो सकता। इस दिशा में प्राइमरी कृषि क्रेडिट सहकारी और सहकारी बैंक अहम भूमिका निभा रहे हैं। देश में पैक्स (प्राइमरी कृषि क्रेडिट सोसाइटीज) की संख्या एक लाख के पार हो गई है। किसान क्रेडिट कार्ड में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हिस्सा 67 प्रतिशत है। सहयोग के जरिए ग्रामीण विकास की जो नींव रखी जा रही है, उसे और मजबूत करने के लिए कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों की क्षमता को पहचानना जरूरी है। चाहे वह दूध उत्पादन हो या हरित क्रांति, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी हमेशा से जरूरी हिस्से रहे हैं। गांवों से आने वाले प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और ब्रांडिंग 'वोकल फॉर लोकल' पहल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। सहयोग अपने पारंपरिक कार्यक्षेत्रों से आगे बढ़कर स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी कदम रख रहा है। इस दिशा में नेशनल सहकारी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू की गई आयुष्मान सहकार योजना के सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं। आज देश में हॉस्पिटल सहकारी सोसाइटीज सफलतापूर्वक काम कर रही हैं।

1.1. स्वतंत्रता के पूर्व भारत मे सहकारिता का विकासः भारत में पहला सहकारी अधिनियम, सहकारी ऋण समितियाँ अधिनियम, 1904 में पारित किया गया था, जिसके बाद 1912 का (संशोधित) सहकारी समितियाँ अधिनियम आया। मैकलैगन समिति 1915 में, सर एडवर्ड मैकलैगन, की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि क्या सहकारी आंदोलन आर्थिक और वित्तीय रूप से सही दिशा में प्रगति कर रहा है। मोंटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 के मोंटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधारों के माध्यम से, सहकारिता एक प्रांतीय विषय बन गया, जिसने आंदोलन को और गति दी। 1929 की आर्थिक मंदी के बाद, मद्रास, बॉम्बे, त्रावणकोर, मैसूर, ग्वालियर और पंजाब में सहकारी समितियों के पुनर्गठन की संभावनाओं की जांच के लिए विभिन्न समितियाँ नियुक्त की गईं। गांधीवादी दर्शन के अनुसार, एक समाजवादी समाज के निर्माण और सत्ता के पूर्ण विकेंद्रीकरण को प्राप्त करने के लिए सहकारिता आवश्यक थी। उनके अनुसार, सहकारिता लोगों को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक समाजवादी मॉडल पर आधारित एक सहकारी संस्था के रूप में 'फीनिक्स सेटलमेंट' की स्थापना की। इस अवधि के दौरान, उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित परिवारों के लिए एक पुनर्वास सहकारी बस्ती के रूप में टॉल्स्टॉय फार्म की भी स्थापना की थी।

1.2. स्वतंत्रता के बाद के भारत में सहकारिता का विकासः पहली पंचवर्षीय योजना (1951–56) ने व्यापक सामुदायिक विकास के लिए सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया। बहु–राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 बहु–राज्य सहकारी समितियों के गठन और कामकाज का प्रावधान करता है। बहु–राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2022 ने बहु–राज्य सहकारी समितियों में बोर्ड चुनावों की देखरेख के लिए एक सहकारी चुनाव प्राधिकरण की शुरुआत की। 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011 ने सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19) के रूप में स्थापित किया। सहकारी समितियों पर राज्य नीति का एक नया निर्देशक सिद्धांत पेश किया गया (अनुच्छेद 43–B)। संविधान में ''सहकारी समितियाँ'' शीर्षक से एक नया भाग IX–B जोड़ा गया (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT)। संसद को बहु–राज्यीय सहकारी समितियों को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जबकि राज्य विधानमंडलों को अन्य सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया।

2. भारत में सहकारिता : भारत में सहकारिता एक खास सोशियो–इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को दिखाती हैं जो देश के ताने–बाने में गहराई से जुड़ा हुआ है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, फायदों के बराबर बंटवारे और वॉलंटरी एसोसिएशन के सिद्धांतों पर आधारित, ये सोसाइटीज अलग–अलग सेक्टर में इनक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए कैटलिस्ट का काम करती हैं। ग्रामीण और कृषि क्रेडिट से लेकर कंज्यूमर वेलफेयर और इंडस्ट्रियल कोलेबोरेशन तक, सहकारी सोसाइटीज

कलेक्टिव एंटरप्राइज को बढ़ावा देने और अपने मेंबर्स की अलग–अलग जरूरतों को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। सहकारी सोसाइटीज की एक खास बात यह है कि वे डेमोक्रेटिक फैसले लेने पर जोर देती हैं, जिससे यह पक्का होता है कि ऑर्गनाइजेशन के गवर्नेंस और ऑपरेशन्स में हर सदस्य की आवाज हो। यह पार्टिसिपेटरी अप्रोच ओनरशिप की भावना को बढ़ावा देता है और सहकारी स्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देता है।

भारत में, सहकारी सोसाइटीज कृषि, क्रेडिट और बैंकिंग, हाउसिंग, विमेन वेलफेयर जैसे कई अलग–अलग सेक्टर में फैली हुई हैं। वे वित्तीय समावेशन के लिए जरूरी जरिया के तौर पर काम करती हैं, किसानों और छोटे एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देती हैं, जिन्हें वरना ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, ये सोसाइटीज लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करके और सोशियो–इकोनॉमिक असमानताओं को कम करके ग्रामीण डेवलपमेंट में अहम योगदान देती हैं। हाल के सालों में, भारत सरकार ने पॉलिसी पहल और फाइनेंशियल मदद से सहकारी सेक्टर को फिर से जिंदा और मजबूत किया है। सहकारी सोसाइटियों को बनाने और बढ़ाने के लिए कई स्कीम और सब्सिडी शुरू की गई हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ वे खेती के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। 'सहकार से समृद्धि' के विजन के तहत, सहकारी मंत्रालय ने पूरे देश में सहकारी एक्टिविटीज को बढ़ावा देने और उनमें तालमेल बिठाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। वर्तमान में, भारत में 29 से अधिक क्षेत्रों में अर्थात् कृषि प्रसंस्करण, औद्योगिक सहकारी समितियां, मधुमक्खी पालन, उपभोक्ता, ऋण और बचत, डेयरी, शैक्षिक और प्रशिक्षण, मत्स्य सहकारी समितियां, हस्तशिल्प, हथकरघा वस्त्र और बुनकर, आवास, जूट और कॉयर, श्रम, पशुधन और मुर्गी पालन, विपणन, विविध ऋण, विविध गैर–ऋण, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस), रेशम उत्पादन, सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक, चीनी मिल, पर्यटन, परिवहन, आदिवासी–एससी/एसटी सहकारी समितियां प्राथमिक सहकारी समितियां हैं।

2.1. पैक्स डेयरी और फिशरी सहकारी ग्रामीण सेक्टर को मजबूत बनाने में अहम रहे हैं। ये सहकारी किसानों को क्रेडिट, टेक्नोलॉजी और मार्केट तक पहुंच देते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और इनकम बढ़ती है। इसके अलावा, वे इनपुट की कलेक्टिव खरीद और प्रोड्यूस की मार्केटिंग को आसान बनाते हैं, जिससे किसानों को मार्केट में मोलभाव करने की मजबूत स्थिति मिलती है। कृषि/एलाइड सहकारी, 76 फेडरेशन के साथ, 26,797 सोसाइटी के साथ 98,36,270 सदस्य हैं। इस सेक्टर में गुजरात में सबसे ज्यादा सोसाइटी (6,643) है, उसके बाद मध्य प्रदेश (3,742) और महाराष्ट्र (3,474) हैं। खास तौर पर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सदस्य (56,49,109) है, उसके बाद महाराष्ट्र (9,93,065) और मध्य प्रदेश (7,00,666) हैं। जहां तक फिशरी सहकारी की बात है, 46,74,279 सदस्य के साथ 25,609 सोसाइटी हैं। तेलंगाना में सबसे अधिक सोसाइटी (4,985) हैं, उसके बाद महाराष्ट्र (3,403) और मध्य प्रदेश (2,798) हैं।

2.2. एग्रो–प्रोसेसिंग/इंडस्ट्रियल सहकारिता, जिसमें 22 फेडरेशन हैं, में 22,735 सोसाइटी हैं और सदस्य 25,31,349 है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक सोसाइटी (5,288) हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश (4,025) और पंजाब (1,987) हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक सदस्य (12,53,407) है, उसके बाद कर्नाटक (4,58,625) और गुजरात (2,14,407) हैं। डेयरी सहकारी सेक्टर में 73 फेडरेशन हैं, जिसमें 1,41,807 सोसाइटी हैं और 1,56,87,794 सदस्य हैं। सबसे अधिक डेयरी सहकारिता उत्तर प्रदेश (17,985) में दर्ज हैं, उसके बाद कर्नाटक (17,645) और गुजरात (16,346) हैं। खास तौर पर, गुजरात में सबसे अधिक सदस्य (36,39,508) हैं।

2.3. सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसाइटी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। वे ग्रामीण और सेमी–अर्बन इलाकों में लोगों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करते हैं, और सेविंग्स, क्रेडिट और इंश्योरेंस जैसी कई फाइनेंशियल सर्विस देते हैं। ये संस्थाएं पारंपरिक साहूकारों पर निर्भरता को काफी कम करती हैं और मेनस्ट्रीम बैंकिंग तक सीमित पहुंच वाले लोगों को मजबूत बनाती हैं। 11 फेडरेशन वाले अर्बन सहकारी बैंक (UCB) 1,502 सोसाइटी में चल रहे हैं। खास तौर पर, महाराष्ट्र में 428 UCB और 60,21,811 सदस्य हैं, जो सबसे अधिक हैं। इसके बाद कर्नाटक है, जहाँ 279 सोसाइटियाँ हैं और 23,35,863 सदस्य हैं, और गुजरात है जहाँ 187 सोसाइटियाँ हैं और 14,91,531 सदस्य हैं। क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सहकारिता की 79,999 सोसाइटियों में 4,32,75,731 सदस्य हैं। तेलंगाना में सबसे अधिक सोसाइटियाँ (24,024) हैं, जबकि सबसे अधिक सदस्य महाराष्ट्र (2,27,27,861) में हैं।

2.4. मिसलेनियस क्रेडिट और नॉन–क्रेडिट सहकारिता में क्रम से 5,575 और 30,364 सोसाइटीज हैं। इनमें क्रम से 89,19,537 और 25,05,838 सदस्य हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक (7,073) मिसलेनियस नॉन–क्रेडिट सोसाइटीज हैं, जबकि सबसे अधिक सदस्य (8,59,093) कर्नाटक की सोसाइटीज से जुड़े हैं। मिसलेनियस क्रेडिट में सबसे अधिक सोसाइटीज (3,238) पश्चिम बंगाल में एनरोल्ड हैं, जबकि कर्नाटक में सबसे अधिक सदस्य काउंट 52,80,248 है। मिसलेनियस क्रेडिट सेक्टर में 21 फेडरेशन हैं जबकि मिसलेनियस नॉन–क्रेडिट में पूरे राज्य/संध में 96 फेडरेशन हैं। इसके 13,99,27,330 सदस्य को 1,03,725 प्राइमरी कृषि क्रेडिट सोसाइटीज सर्विस दे रही हैं। महाराष्ट्र 20,949 सोसाइटियों के साथ सबसे आगे है, उसके बाद गुजरात (10,248) और बिहार (8,463) हैं। खास तौर पर, केरल में

सबसे अधिक PACS सदस्य (2,56,28,261) है, उसके बाद बिहार (1,36,08,525) है। भारत में सहकारी मूवमेंट हाउसिंग, हैंडलूम और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर में भी फैल गया है। हाउसिंग सहकारिता मेंबर्स को मिलकर अपनी हाउसिंग की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती हैं, खासकर शहरी इलाकों में जहाँ सस्ते घर एक बड़ी चिंता है। सहकारिता के 1,91,734 सोसाइटियों में 1,46,65,027 सदस्य हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक हाउसिंग सहकारिता (1,25,734) हैं, उसके बाद गुजरात (29,529) है। हाउसिंग सहकारी सेक्टर में राज्यों/संघों में 47 फेडरेशन/यूनियन रजिस्टर्ड हैं। हैंडलूम सहकारिता पारंपरिक कारीगरों को सपोर्ट करती हैं, देसी क्राफ्ट्स को बचाती हैं, और सस्टेनेबल रोजी–रोटी के लिए एक प्लेटफॉर्म देती हैं। हैंडलूम टेक्सटाइल और वीवर सहकारिता में 19,576 सोसाइटियों में 51,56,723 सदस्य हैं। मणिपुर में सबसे अधिक (5,588) सोसाइटियाँ हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश (1,841) का स्थान आता है। खास बात यह है कि सबसे अधिक सदस्य (29,85,671) कर्नाटक में है, उसके बाद तमिलनाडु (3,01,969) का स्थान आता है। जूट और कॉयर सहकारिता में 56 सोसाइटियाँ हैं जिनमें 5,755 सदस्य हैं। इस सेक्टर में कर्नाटक में सबसे अधिक सोसाइटियाँ (17) हैं। एक और जानी–मानी सहकारी, कंज्यूमर सहकारी, में 21,067 सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड हैं जिनमें 63,75,920 सदस्य हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कंज्यूमर सहकारिता के तहत सबसे अधिक सोसाइटियाँ मध्य प्रदेश (4,959) में हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ (2,417) का स्थान आता है। सबसे अधिक सदस्य मध्य प्रदेश (12,53,231) में दर्ज हैं, उसके बाद महाराष्ट्र (10,61,516) का स्थान आता है। कंज्यूमर सेक्टर में पूरे राज्य में 30 फेडरेशन/यूनियन रजिस्टर्ड हैं। दूसरी मशहूर सहकारी, जैसे शुगर मिल सहकारी, एक खास तरह की सहकारी सोसाइटी हैं जो शुगर इंडस्ट्री में काम करती हैं। सहकारी का मकसद किसानों को गन्ने की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पर कंट्रोल देकर उन्हें मजबूत बनाना है, ताकि उन्हें उपज का सही रिटर्न मिल सके। इस सेक्टर में 284 सहकारी सोसाइटी हैं जिनके कुल 47,83,246 सदस्य हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक (94) शुगर मिल सहकारी हैं जिनके 16,27,196 सदस्य हैं, इसके बाद कर्नाटक और बिहार का स्थान आता है, दोनों में सहकारी के तहत 35–35 सोसाइटी हैं।

Table-1: State-wise Cooperatives and Members

S. No.	Sectors	Total no. of Societies	Total no. of Members	S. No.	Sectors	Total no. of Societies	Total no. of Members
1	Agriculture & Allied	26798	2531349	15	Marketing	9121	4590611
2	Agro Processing / Industrial	22735	38181	16	Miscellaneous Credit	5575	8919537
3	Bee Farming	325	6375920	17	Miscellaneous Non Credit	30364	2505838
4	Consumer	21067	43275731	18	Multipurpose Cooperative	19964	2582130
5	Credit & Thrift	79999	15687794	19	PACS/FSS/LAMPS	104234	139927330
6	Dairy	141807	78717	20	Sericulture Cooperative	498	67149
7	Educational & Training	387	4674279	21	Social Welfare & Cultural	2055	291308
8	Fishery	25649	369840	22	Sugar Mills	284	4783246
9	Handicraft Cooperative	5063	5156723	23	Tourism	459	280400
10	Handloom Textile & Weavers	19576	14665027	24	Transport	4163	704336
11	Housing	191734	5755	25	Tribal-SC/ST	1472	1033894
12	Jute and Coir	56	1491300	26	Urban Cooperative Bank	1335	14646837
13	Labour	44545	1339349	27	Women's Welfare	24261	5221424
14	Livestock & Poultry	16677	9836270	**Total**		800203	291280275

National Cooperative Database 2023: A Report

2.5. सेरीकल्चर सहकारिता और बीकीपिंग सहकारिताः यह एक खास सहकारी सोसाइटी हैं जो एक के बाद एक सिल्क प्रोडक्शन और बीकीपिंग पर फोकस करती हैं। सेरीकल्चर सहकारिता की 498 सोसाइटीज में 67,149 सदस्य हैं। कर्नाटक में सबसे अधिक सोसाइटीज (97) हैं, उसके बाद ओडिशा (54) का स्थान है। खास बात यह है कि ओडिशा में सबसे अधिक 31,608 सदस्य हैं। बी फार्मिंग सहकारिता में 325 सोसाइटीज हैं जिनमें 38,181 सदस्य हैं। बिहार में सबसे अधिक सोसाइटीज (124) हैं, उसके बाद मणिपुर (85) का स्थान है। राजस्थान में सबसे अधिक 13,956 सदस्य हैं, उसके बाद कर्नाटक (10,988) का स्थान है। दोनों सहकारिता गांव की रोजी–रोटी, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और वैल्यू–एडेड प्रोडक्ट्स के सस्टेनेबल प्रोडक्शन में योगदान देती हैं।

2.6. एजुकेशनल और ट्रेनिंग सहकारिता खास सहकारी एंटिटीज हैं जो स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम देती हैं। ये सहकारिता एजुकेशन और ट्रेनिंग के मौके देने में बहुत जरूरी हैं, खासकर उन कम्युनिटीज में जिनके पास कम रिसोर्स हैं। इन सहकारिता में 387 सोसाइटीज में 78,717 सदस्य एनरोल्ड हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक सोसाइटी

(73) हैं, उसके बाद राजस्थान (63) का स्थान है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक सदस्य (32,533) हैं, उसके बाद असम (13,746) का स्थान है। सहकारी के 78 फेडरेशन यूनियन पूरे राज्य में रजिस्टर्ड हैं।

2.7. महिला कल्याण सहकारी सहकारी के सिद्धांतों के जरिए महिलाओं की भलाई और सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। ये सहकारी महिलाओं की सोशियो–इकोनॉमिक चुनौतियों का समाधान करते हैं, जिसमें एजुकेशन, हेल्थकेयर, आर्थिक सशक्तिकरण और सोशल सपोर्ट शामिल हैं। इस सेक्टर में 24,261 सोसाइटी हैं जिनमें 54,21,424 सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सहकारी (11,073) हैं, उसके बाद राजस्थान (4,218) और असम (2,885) का स्थान है। खास बात यह है कि तेलंगाना में सबसे अधिक रजिस्टर्ड सदस्य (30,96,825) हैं, उसके बाद राजस्थान (6,23,324) और असम (6,18,927) का स्थान है। सोशल वेलफेयर और कल्चरल सहकारी सोशल, कल्चरल और कम्युनिटी से जुड़े मकसदों को पूरा करते हैं। सहकारी का मकसद अपने सदस्यों की भलाई को बढ़ाना और समाज के पूरे विकास में योगदान देना है। ऑल इंडिया सहकारी सेक्टर में 2,91,308 सदस्यों के साथ 2,055 सोशल वेलफेयर और कल्चरल सहकारी हैं। तेलंगाना और महाराष्ट्र में सबसे अधिक सोसाइटी हैं, यानी 1,095 और 424, जिनमें क्रमशः 2,00,666 और 31,523 सदस्य हैं। ट्राइबल सेक्टर को फायदा पहुंचाने वाली एक और खास सोसाइटी ट्राइबल SC/ST सहकारी है। सहकारी का मकसद SC/ST और ट्राइबल आबादी को रिसोर्स, आर्थिक रिसोर्स और मिलकर फैसले लेने के लिए एक प्लेटफॉर्म देकर उन्हें मजबूत बनाना है। सहकारी के 1,472 सोसाइटियों में 10,33,894 सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारी की सबसे अधिक संख्या (847) है, उसके बाद पंजाब (255) और हरियाणा (80) का स्थान आता है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक (7,63,886) सदस्य है। इस सेक्टर में 3 फेडरेशन हैं।

2.8. लेबर सहकारिता में सेल्फ–हेल्प, इक्विटी, डेमोक्रेसी और वर्कर्स के बीच एकजुटता के सिद्धांत शामिल हैं। सहकारी अपने मेंबर्स की कलेक्टिव वेल–बीइंग पर जोर देता है, साथ ही सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए कोशिश करता है। सहकारिता के 44,545 सोसाइटियों में 14,91,300 सदस्य हैं। महाराष्ट्र में सहकारिता की सबसे अधिक सदस्य (3,77,278) है, उसके बाद गुजरात (3,43,376) है। इन सहकारिता के राज्य/संघ में 65 फेडरेशन रजिस्टर्ड हैं।

2.9. ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म सहकारिता लोकल कल्चर और कम्युनिटीज की वेल–बीइंग की सुरक्षा करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 4,163 रजिस्टर्ड सोसाइटियाँ हैं, जबकि टूरिज्म सेक्टर में देश भर में 459 सोसाइटियाँ हैं। हरियाणा में ट्रांसपोर्ट में सबसे अधिक सोसाइटियाँ (1,935) रजिस्टर्ड हैं, जिनकी सदस्य 4,87,181 है। हरियाणा के बाद झारखंड में 259 सोसाइटियाँ हैं, जबकि सदस्य में महाराष्ट्र में 58,638 के साथ दूसरी सबसे अधिक सदस्य है। टूरिज्म में महाराष्ट्र 125 सोसाइटियों के साथ सबसे आगे है, उसके बाद मेघालय (55) और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स (46) हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक सदस्य (2,15,908) हैं, उसके बाद अंडमान और निकोबार आइलैंड्स (53,529) हैं।

Figer-1: Trend in Sector-wise No. of Societies in the Country.

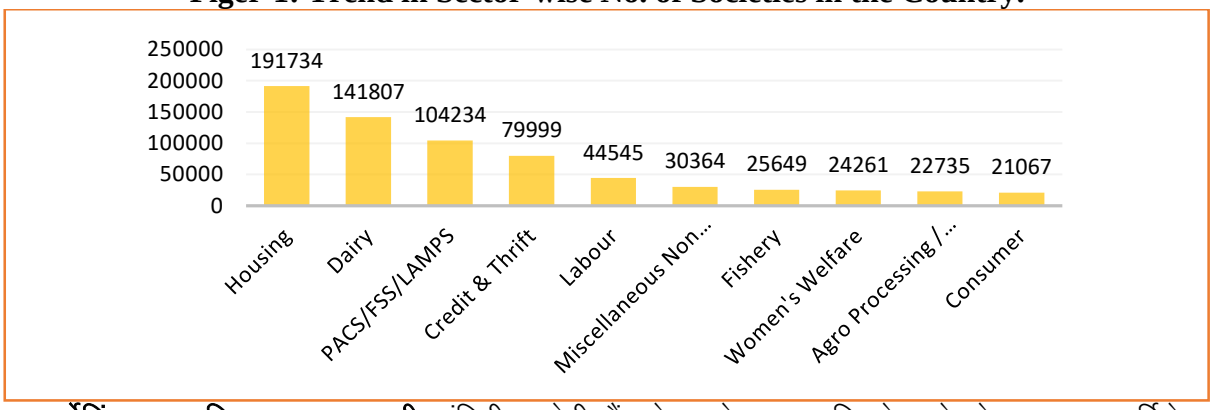

2.10. मार्केटिंग सहकारिता खास सहकारी: एंटिटीज होती हैं जो अपने सदस्य बिजनेस के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करने और बेचने पर फोकस करती हैं। ये सहकारी अलग–अलग प्रोड्यूसर, किसान या बिजनेस मिलकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने, लागत कम करने और मार्केट में अपनी मोलभाव करने की ताकत बढ़ाने के लिए बनाते हैं। मार्केटिंग सहकारी में 9,121 सोसाइटियों से जुड़े 45,90,611 सदस्य हैं। इस सेक्टर में सबसे अधिक सोसाइटियाँ उत्तर प्रदेश में हैं, यानी 1,791, इसके बाद गुजरात में 1,713 सोसाइटियाँ हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक सदस्य (8,85,211) हैं, इसके बाद महाराष्ट्र (6,75,050) और कर्नाटक (5,41,030) हैं। असल में, भारत में सोसाइटियाँ सामाजिक–आर्थिक विकास के इंजन के तौर पर काम करती हैं, जो समुदाय और साझा खुशहाली की भावना को बढ़ावा देती हैं।

जैसे–जैसे भारत तेजी से बदलते आर्थिक माहौल की मुश्किलों से निपट रहा है, सहकारी सेक्टर सबको साथ लेकर चलने वाले विकास और मजबूती के बड़े ताने–बाने का एक तेजी से बढ़ने वाला और जरूरी हिस्सा बना हुआ है।

Figer-2: Trend in Sector wise number of Members in the Country

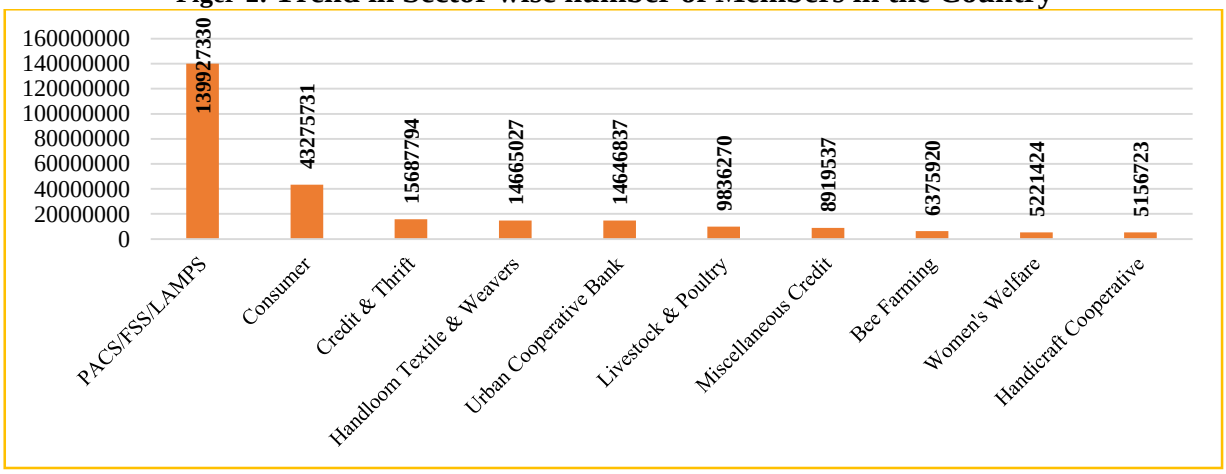

3. भारत में सहकारी समितियों की वर्तमान स्थिति : अमूल डयेरी भारत की सबसे बड़ी डेयरी सहकारी समितियां जिसने ''श्वेत क्रांति'' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया जिसका कारोबार 7.3 बिलियन से अधिक है। इफको उर्वरक भारत की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी समिति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी समितियां 7.3 बिलियन से अधिक राजस्व सहित इसकी उल्लेखनीय वृद्धि ने इसे फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची में स्थान दिलाया। कर्नाटक दुग्ध संघ (नंदिनी) डयेरी भारत में दूसरी सबसे बड़ी डेयरी सहकारी समितियां कर्नाटक में 15 दुग्ध संघों के साथ काम करती है, प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों से दूध खरीदती है। शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में अपनी सेवाएं देती है, जिससे 1,500 से अधिक सदस्य लाभान्वित होते हैं। इंडियन कॉफी हाउस सोसाइटी उपभोक्ता/रेस्तरां श्रमिक सहकारी समितियों के नेटवर्क द्वारा प्रबंधित इसके लगभग 400 कॉफी आउटलेट हैं। उरालुंगल श्रम अनुबंध सहकारी समिति, श्रम सहकारी समिति भारत की सबसे पुरानी श्रम सहकारी समितिय लगभग 1415 व्यक्तियों की सदस्यता के साथ यूएलसीसीएस ने 7500 से अधिक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है

भारत में सहकारी समितियों की त्वरित उन्नति अब कोई काल्पनिक आदर्श नहीं रह गया है। यह एक जमीनी, मूलभूत क्रांति है। सहकारी समितियाँ न केवल लोगों को सशक्त बना रही हैं, बल्कि वे समावेशी, लोकतांत्रिक विकास की नए सिरे से परिकल्पना भी कर रही हैं। एक सदी पहले एक जन आंदोलन के रूप में शुरू हुई। यह मुहिम अब भारत के न्यायसंगत और समावेशी विकास की कुंजी बन सकती है।

4. भारत की अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र का महत्व : भारत में, सहकारी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर जब सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की बात आती है। ग्रामीण और वंचित समुदाय सहकारी समितियों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं क्योंकि उनका प्राथमिक उद्देश्य आपसी सहायता और सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देकर अपने सदस्यों की जरूरतों को पूरा करना है। भारत के सहकारी क्षेत्र ने देश की अर्थव्यवस्था को कई महत्वपूर्ण तरीकों से बढ़ावा दिया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

4.1. वित्तीय समावेशन: सहकारी समितियों और विशेष रूप से सहकारी बैंकों ने ग्रामीण समुदायों में बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे कम आय वाले व्यक्तियों, छोटे उद्यमों और किसानों के लिए, जो बड़े बैंकों से ऋण के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं, आवश्यक धन प्राप्त करने का एक सरल तरीका प्रदान करते हैं। यह ग्रामीण गरीबी को कम करने और कृषि विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

4.2. कृषि विकास: सहकारी क्षेत्र भारत की कृषि प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यह किसानों को बीज, उर्वरक और मशीनरी जैसे इनपुट प्रदान करके सहायता करता है, इसके अलावा ऐसी सहकारी समितियों को भी सुविधा प्रदान करता है जो कटाई के बाद की गतिविधियों जैसे प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन की देखरेख करती हैं। इस क्षेत्र ने छोटे और सीमांत किसानों को संसाधनों, उत्पादकता और बाजार में सौदेबाजी की शक्ति तक उनकी पहुंच बढ़ाकर सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

4.3. ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना: सहकारी आंदोलन ग्रामीण भारत की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में सहायक रहा है। समुदायों के भीतर स्वयं सहायता समूहों के गठन ने व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने में सक्षम बनाया है। परिणामस्वरूप, परिवारों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और लैंगिक समानता और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिला है।

4.4. रोजगार सृजन: बैंकिंग, कृषि, खुदरा और विनिर्माण सहित कई क्षेत्रों को रोजगार के अवसर पैदा करने की सहकारी क्षेत्र की क्षमता से बहुत फायदा होता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, यह लोगों को आजीविका कमाने के वैकल्पिक तरीके प्रदान करके बेरोजगारी को कम करने में मदद करता है। समुदाय निर्माण पर अपने जोर के कारण, सहकारी समितियां आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण में योगदान करती हैं और रोजगार की तलाश में ग्रामीण निवासियों के शहरों की ओर पलायन को धीमा करती हैं।

4.5. सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना: एक सहकारी समिति का प्राथमिक लक्ष्य केवल वित्तीय लाभ नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों का कल्याण है। भारत में कई सहकारी समितियां अपने सदस्यों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आवास तक पहुंच प्रदान करती हैं। ये योगदान वंचित क्षेत्रों में लोगों की सामाजिक सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता दोनों में सुधार करते हैं।

4.6. आर्थिक स्थिरता और जोखिम कम करना: संसाधनों को एक साथ लाकर और जोखिमों को शेयर करके, सहकारी आय को स्थिर करने, वित्तीय कमजोरी को कम करने और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। यह खासकर कृषि जैसे उद्योगों में बहुत जरूरी है, जहाँ किसानों को बाजार की कीमतों में उतार–चढ़ाव और जलवायु परिवर्तन जैसे कई जोखिमों का सामना करना पड़ता है। सहकारी मॉडल इन जोखिमों के असर को फैलाने और कम करने में मदद करता है।

4.7. स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना: व्यक्तिगत पहल और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा देकर, सहकारी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देते हैं। वे स्थानीय स्तर पर खरीदने और बेचने को प्राथमिकता देते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि पैसा समुदाय के भीतर ही घूमे और आर्थिक लाभ घर के पास ही रहें। इससे स्थानीय कारीगरों, छोटे व्यवसायों और उद्योगों को फलने–फूलने में मदद मिलती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

5. आर्थिक स्थिरता और विकास : देश के खासकर अधिक दूरदराज के इलाकों में, सहकारी स्थायी विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। स्थायी वन प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और जैविक खेती कुछ ऐसी पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाएँ हैं जिन पर कई भारतीय सहकारी अभी ध्यान दे रहे हैं। एक हरित और अधिक स्थायी अर्थव्यवस्था एक बड़ा लक्ष्य है, और सहकारी पूरी तरह से आर्थिक उद्देश्यों के बजाय पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देकर इसे हासिल करने में योगदान देते हैं। कुल मिलाकर, भारत में सहकारी क्षेत्र सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और आर्थिक समावेशन का विस्तार करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, जिन चुनौतियों का यह सामना करता है, इसके बावजूद, भारत के लिए एक अधिक निष्पक्ष और स्थायी आर्थिक भविष्य बनाने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। देश को समावेशी और स्थायी विकास के अपने उद्देश्यों को गुजरात में अमूल डेयरी सहकारी, जिसके 3.6 मिलियन से अधिक दूध उत्पादक हैं (जिनमें से अधिकतर छोटे और सीमांत किसान हैं), दूध के लिए सही दाम देकर और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर, खासकर महिलाओं के लिए, ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाता है।

कृषि उत्पादकता और मार्केटिंग को बढ़ावा देना, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर सहकारी लिमिटेड दुनिया का सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक है। IFFCO जैसे सहकारी किसानों को उर्वरक, बीज और क्रेडिट जैसे जरूरी कृषि इनपुट प्रतिस्पर्धी कीमतों पर देते हैं, जिससे उत्पादकता और कृषि आय बढ़ती है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र में चीनी सहकारी 500,000 से अधिक लोगों को (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से) रोजगार देते हैं, जो ग्रामीण रोजगार और आय सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कृषि, ऋण, डेयरी, आवास और मत्स्य पालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 8,50,000 से अधिक सहकारी समितियों के साथ, भारत का सहकारी नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। सहकारी क्षेत्र कृषि ऋण वितरण में 20 प्रतिशत, उर्वरक वितरण में 35 प्रतिशत, चीनी उत्पादन में 31 प्रतिशत, गेहूं खरीद में 13 प्रतिशत और धान खरीद में 20 प्रतिशत का योगदान देता है।

6. सहकारिता के लिए शासन संबंधी चुनौतियाँ :

1. सहकररिता को अक्सर पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की कमी से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सदस्यों की सीमित भागीदारी, हाशिए पर पड़े समुदायों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, और कुछ व्यक्तियों के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण सहकारी उद्यमों के समावेशी स्वरूप को कमजोर कर सकता है।

2. कई सहकारिता, खासकर जो हाशिए पर पड़े समुदायों की सेवा करते हैं, उन्हें वित्तीय संसाधनों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनके पास अक्सर पारंपरिक वित्तीय संस्थानों द्वारा आवश्यक गिरवी या औपचारिक दस्तावेजों की कमी होती है, जिससे ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।
3. सहकारिता को अक्सर समावेशिता की कमी, संरचनात्मक असमानताओं आदि से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
4. अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और कनेक्टिविटी की कमी उनकी दक्षता और प्रभावशीलता को प्रभावित करती है, जिससे पहुँच सीमित हो जाती है।
5. प्रशिक्षण और कौशल विकास पहलों की अनुपस्थिति एक और चुनौती है, जिससे पुराने मानव संसाधन होते हैं।
6. संभावित सदस्यों में सहकारी मॉडल और इसके लाभों के बारे में जागरूकता की कमी उनकी भागीदारी को सीमित करती है।

निष्कर्ष : वित्तीय समावेशन, कृषि विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर, भारत में सहकारी क्षेत्र ने सामाजिक–आर्थिक विकास में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी अनूठी अवधारणा, जो सभी सदस्यों की भलाई को प्राथमिकता देती है, ने वंचित समुदायों को अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने में मदद की है और सतत विकास को एक वास्तविकता बनाया है। लेकिन ऐसे कई बाधाएँ हैं जो इस क्षेत्र के विकास और स्थिरता में रुकावट बन सकती हैं, जैसे कि अक्षम प्रबंधन, राजनीतिक हस्तक्षेप और आधुनिक तकनीक तक पहुँच की कमी। इन सभी बाधाओं के बावजूद, सहकारी उद्योग अभी भी बहुत अधिक संभावनाओं से भरा हुआ है। सहकारी समितियाँ तकनीक को अपनाकर, शासन संरचनाओं को उन्नत करके निवेश और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने वाला माहौल बनाकर मौजूदा बाधाओं को दूर कर सकती हैं और भारत के आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रख सकती हैं। उद्योग को फिर से जीवंत करने और भारतीय आबादी की बदलती आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए, सरकार को रणनीतिक बदलावों का समर्थन करना चाहिए और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना चाहिए। अंत में, हालांकि भारत के सहकारी क्षेत्र ने निस्संदेह देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, यह महत्वपूर्ण है कि यह अपने महत्व और प्रभाव को बनाए रखने की गारंटी के लिए आधुनिकीकरण और सुधार से गुजरे। सहकारी क्षेत्र द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग, बेहतर शासन और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से एक अधिक समृद्ध, न्यायसंगत और टिकाऊ भारत प्राप्त किया जा सकता है। योजनाकारों और विशेषज्ञों में एक कमी यह रही है कि उन्होंने सहकारी इकाइयों को केवल ''इनपुट'' प्रदान करने वाली संस्थाएं माना, जबकि वास्तविकता में, ये संस्थाएं न केवल सभी प्रकार के काम करने में सक्षम हैं, बल्कि ऐसा कर भी रही हैं, और इस प्रकार ग्रामीण विकास के ''मुख्य केंद्र'' के रूप में कार्य कर रही हैं। वर्तमान स्थिति में उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करना न केवल आवश्यक बल्कि अनिवार्य हो गया है। सहयोग की संगठनात्मक संरचना, कार्यप्रणाली, सिद्धांत, सामुदायिक भागीदारी, वित्तीय सुदृढ़ता, विस्तार आदि ऐसी नींव हैं जो यह साबित करती हैं कि सहयोग ग्रामीण विकास का मुख्य और एकमात्र साधन है।

स्रोत एवं संदर्भः

1. सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार.
2. कुरुक्षेत्र पत्रिका, जुलाई 2025 संस्करण.
3. https://cooperatives.gov.in/en
4. https://www.cooperation.gov.in/en/2023-2024
5. https://x.com/Minofcooperatn/status/1816337535905550687
6. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146772
7. https://www.cooperation.gov.in/en/major-initiative-of-the-ministry
8. https://vamnicom.gov.in/uploads/4f51e1ee3035ac8005355277540565be.pdf
9. https://vamnicom.gov.in/uploads/ebc76414f685d0ee399c9b8f993505d0.pdf
10. https://www.cooperation.gov.in/sites/default/files/2025-03/IYC%20Annual%20Action%20Plan-English.pdf
11. https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pm-inaugurates-ica-global-cooperative-conference-2024/

आलेख उद्धरित करें :	सिंह, पवन कुमार एवं कुमार, डॉ. मुकेश (2026)। भारत में सहकारी समितियों के प्रगति और प्रदर्शन का अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–1, जनवरी–मार्च, 2026, पृष्ठ 59–66। https://doi.org/10.5281/zenodo.21625586